जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 49 संख्याः 285 प्रभात कोटा, रविवार 28 जुलाई, 2024 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का कार्यकाल छः माह और बढ़ा

ऐसा माना जा रहा है कि प्र.मंत्री मोदी व संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच पार्टी को कंट्रोल करने के लिये चल रही खींचतान के कारण नड्डा को एक्सटैंशन देना आवश्यक हो गया था

- रेणु मित्तल -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा अगले 6 माह तक पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा अब वे कार्यकाल विस्तार पर हैं।

उनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, जबकि उनके स्थान पर कोई अन्य नेता अध्यक्ष बनना था। इसीलिये तो उन्हें एन.डी.ए. सरकार के गठन के समय केन्द्रीय मन्त्री बनाया गया था।

नया अध्यक्ष न बनाये जाने के पीछे मूल कारण आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच चल रही रस्साकशी है। भागवत चाहते हैं कि उनकी पसंद का कोई कट्टर आर.एस.एस. समर्थक व्यक्ति भाजपा अध्यक्ष बने, जिससे पार्टी का नियन्त्रण फिर से उनके हाथों में आ जाये, जो मोदी-शासन के दस वर्षों के दौरान, उनके हाथों से निकल गया है।

दूसरी तरफ, मोदी अपनी पसन्द का कोई व्यक्ति चाहते हैं, जिससे पार्टी तथा सरकार दोनों में ही सत्ता उनके नियन्त्रण में रहे। इसलिए, नए अध्यक्ष का निर्णय अभी टाल दिया गया है।

अगले छः महीने, मोदी 75 वर्ष की आयु को पार कर लेंगे। यही आयु-सीमा रिटायर होने के लिये तय की गई है, जिससे अपेक्षाकृत युवा नेता सत्ता के संचालन तन्त्र में आ सकें।

यहाँ यह याद दिलाना उचित होगा कि एल.के.आडवाणी तथा मुरली मनोहर जोशी तथा अन्य उम्रदराज नेताओं को रिटायर कर सत्ता से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वे लोग 75 वर्ष के हो चुके थे। आर.एस.एस. मोदी शासन का अन्त करने तथा उनके स्थान पर अपनी पसंद का नेता लाने के लिये कारणों की तलाश रही है। जब 2024

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- यह भी माना जा रहा है कि मोहन भागवत नया भाजपा अध्यक्ष पूर्णतया आर.एस.एस. का कट्टर समर्थक चाहते हैं। जिससे पुनः भाजपा पर उनका पूर्णतया नियंत्रण हो।
- मोदी शासन के गत दस वर्षों में संघ का भाजपा में प्रभाव कम हो गया था तथा नये पार्टी अध्यक्ष के मार्फत भागवत पुनः भाजपा पर संघ का प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं।
- छः माह में मोदी 75 वर्ष के हो जायेंगे तथा आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी की भांति उन्हें भी रिटायर होना पड़ेगा तथा बागडोर युवा पीढ़ी के नेता को सौंपनी पड़ेगी।
- आर.एस.एस. मोदी को लोकसभा चुनाव के बीच ही रिटायर करना चाहती थी, जब भाजपा लोकसभा में अल्पमत में आ गयी थी, पर, मोदी ने सीधे एन.डी.ए. की ओर से प्र.मंत्री पद का उम्मीदवार बनकर भाजपा के संसदीय बोर्ड की भूमिका गौण कर दी थी।
- अब मोदी की आयु 75 वर्ष होने के बाद एक संघर्ष की स्थिति बनेगी तथा आर.एस.एस. मूल के सांसदों की भूमिका निर्णायक हो जायेगी। ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का रोल भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निरंतर चर्चा जोर पकड़ती जा रही है कि मोदी-शाह द्वय योगी को हटाना चाहते हैं।

जे.डी.ए. सचिव गिरफ्तारी वॉरंट और जे.डी.सी. जमानती वॉरंट से तलब

जयपुर, 27 जुलाई (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, चतुर्थ ने पृथ्वीराज नगर (पी.आर.एन.) में भूखंड देने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट तक केस हारने के बाद भी, 11 साल में आयोग के आदेश की पालना नहीं करने पर जे.डी.ए. सचिव हेमपुष्पा शर्मा के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

- जिला उपभोक्ता आयोग ने पृथ्वीराज नगर योजना में भूखंड देने के एक मामले में यह आदेश दिए। इस मामले में जे.डी.ए. सुप्रीम कोर्ट में भी हार चुका है फिर भी परिवादी शंभुदयाल अग्रवाल को भूखंड नहीं दिया गया।

आयोग ने गांधी नगर एस.एच.ओ. को निर्देश दिया है कि वे सचिव को गिरफ्तार कर 12 अगस्त को आयोग के समक्ष पेश करें। इसी के साथ आयोग ने जे.डी.सी. मंजू राजपाल को भी 10 हजार रुपए के जमानती वारंट से 12 अगस्त को तलब किया है और वारंट की तामील की जिम्मेदारी गांधीनगर एस.एच.ओ. को दी है। आयोग ने यह आदेश परिवादी शम्भूदयाल अग्रवाल के प्रार्थना पत्र पर दिया। प्रार्थना पत्र में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीति आयोग प्रकरण में ममता बनर्जी की मजबूरी झलकती है?

नीति आयोग की बैठक में उन्होंने महसूस किया कि वे अलग-थलग पड़ गईं और एकमात्र गैर-भाजपा मु.मंत्री बनकर रह गईं, जो नीति आयोग की बैठक में भाग ले रही हैं

- अंजन रॉय -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। हर तरीके से ममता बनर्जी राष्ट्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने के लिए बेताब हो रही हैं क्योंकि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में शुन्य पर चली गई हैं।

ममता बनर्जी ने दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक पर अपने क्रोध का इज़हार किया और दावा किया कि उन्हें बैठक में अपनी बात रखने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उन्होंने उनके साथ हुई घटना के बारे में दावे के साथ कहा कि उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया था।

उनके इस बेबुनियाद आरोप के जवाब में केन्द्र सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, सरकार ने दावे के साथ कहा कि यह आरोप सत्य नहीं है।

दुसरी तरफ, बंगाल से उनके इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधि ने उनके इस दावे को बकवास बताया।

पश्चिम बंगाल से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जो एक बार संसद में विपक्ष के नेता रह चुके हैं उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य भूमिका में आने के कारण उनसे बहुत "ईर्ष्या" करती हैं।

अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी यह जानती थीं कि नीति आयोग की बैठक में क्या होने वाला है इसलिए उन्होंने अपनी ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए जानबूझकर यह सब नाटक किया था। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की उपस्थित में दिल्ली में आयोजित नीति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अतः उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, इसके अलावा नीति आयोग की बैठक के बीच में बायकॉट का नाटक रचकर वॉकआउट करें।
- प्रैस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पी.आई.बी.) ने "फैक्ट चैक" करके अपना निर्णय सुनाया कि ममता बनर्जी का दावा गलत है कि उनका "माइक" बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। पी.आई.बी. के अनुसार उन्हें जो समय आवंटित था, उन्होंने न केवल उसका पूरा उपयोग किया, बल्कि अपने आवंटित समय से ज्यादा समय लिया और उनका समय खत्म होने के बाद भी उनको रोकने के लिये घंटी भी नहीं बजाई थी।
- कांग्रेस के बंगाल के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, ने सार्वजनिक बयान में कहा, ममता बनर्जी को भारी जलन हो रही है राहुल गांधी से, क्योंकि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता ही नहीं बने, बल्कि इण्डिया गठबंधन की राजनीति अब उनके चारों तरफ ही घूम रही है।

राजस्थान से बैंगलुरू भेजा गया 14,000 किलोग्राम संदिग्ध "डॉग मीट" जब्त

समझा जाता है कि बैंगलुरू में रैस्त्रां अपने ग्राहकों को मटन के नाम पर डॉग मीट परोस रहे हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। संभावना है कि बेंगलुरू के रैस्त्रां और भोजनालय अपने ग्राहकों को कुत्ते का मांस (डॉग मीट) परोस रहे हैं। यह बात तब सामने आई, जब पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान से आई एक ट्रेन से कार्टनों में भरकर आया संदिग्ध डॉग मीट जब्त किया।

स्थानीय पुलिस के अनुसार, व्यापारी लोग आमतौर पर ट्रेन से मांस के कार्टन भेजते हैं। कुछ आकलनों के अनुसार, राजस्थान से तकरीबन 14,000 किलो मांस ट्रेन से बेंगलुरू भेजा जाता है। शुक्रवार को स्थानीय पुलिस तथा फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के कर्मियों ने जयपुर- मैसूर एक्सप्रेस से आए संदिग्ध डॉग मीट के 150 कार्टन जब्त किए। फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने एक प्रेस कॉन्फ्रैंस में बताया कि मांस के सैम्पल जांच व परीक्षण के लिए लैबोरेटरी भेजे गए हैं। यह भी कहा गया कि प्रतिबंधित पशु मांस भेजने और रैस्त्रां तथा भोजनालयों को बेचने के दोषी पाए गए लोगों को सख्त सजा दी जाएगी।

गौ रक्षक समूहों के अनुसार, राजस्थान से हर रोज बड़ी तादाद में मांस ट्रेन से बेंगलुरू आता है। शुक्रवार को अधिकारियों ने बेंगलुरू के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर मीट के ट्रकों को पकड़ा, जिन पर शहर में वितरण के लिए मांस के कार्टन लादे जा रहे थे। यह माल जयपुर- मैसूर एक्सप्रेस से आया था। सूचना मिलने पर बी.बी.एम.पी. (बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका) के स्वास्थ्य अधिकारी तुरंत रेलवे स्टेशन पहुँचे।

ज्ञातव्य है कि डॉग मीट के व्यापार पर प्रतिबंध है तथा नागालैण्ड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ कथित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- स्थानीय पुलिस ने बताया कि जयपुर-मैसूर एक्सप्रैस से 14,000 किलोग्राम मांस के कार्टन राजस्थान से बैंगलोर भेजे गए थे।
- स्थानीय पुलिस व फूड सेफ्टा एण्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को खबर मिली कि कार्टनों में संभवतया "डॉग मीट" है।
- बेंगलुरू के यशवंतपुर रेल्वे स्टेशन पर जब ये कार्टन ट्रकों में लादे जा रहे थे तब पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया और सैम्पल टैस्ट के लिए भेजे हैं।
- अगर साबित हो गया कि यह डॉग मीट है तो दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली: कोचिंग सैन्टर के बेसमैंट में पानी भरा, दो स्टूडैंट्स की मौत

नई दिल्ली, 27 जुलाई। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर जाने की जानकारी सामने आई है। सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर में यू.पी.एस.सी. एग्जाम की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। घटना में दो छात्राओं के मौत की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर और एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए पहुंचीं। घटना राव आई.ए.एस. स्टडी सैंटर की बताई जा रही है। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं।

घटना पर डी.सी.पी. सैंट्रल एम हर्षवर्धन ने बताया कि शाम 7 बजे हमें सूचना मिली कि राजेंद्र नगर में एक यू.पी.एस.सी. कोचिंग संस्थान के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- दिल्ली के राजेन्द्र नगर इलाके में बारिश के बाद कोचिंग के बेसमैंट में पानी भर गया, जिससे वहां क्लास ले रहे कई स्टूडैंट्स फंस गये तथा दो छात्राओं की मौत की जानकारी सामने आई है।

ममता बनर्जी ने भविष्य में आयोजित नीति आयोग की किसी भी बैठक में भाग न लेने की धमकी दी

विपक्ष के नेता ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए नज़र आये

- श्रीनन्द झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नीति आयोग की चल रही बैठक से बीच में ही बाहर आई और आरोप लगाया कि उन्हें बैठक में बहुत कम समय बोलने दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि यह भी धमकी दी कि वे भविष्य में आयोजित होने वाली बैठकों में उपस्थित नहीं होंगी। बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं। इस संस्था को या तो वित्तीय शक्तियों से समर्थ बनाया जाए, या फिर जो पहले योजना आयोग था उसे पुनर्जीवित किया जाए।"

विपक्षी नेताओं ने भी बनर्जी की इस शिकायत का साथ दिया कि बैठक में उनके भाषण को छोटा कर दिया क्योंकि उनके भाषण के दौरान उनके माइक की आवाज बंद कर दी गई थी। इस घटना पर स्टालिन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "क्या यही सहभागिता वाला संघवाद है? क्या एक मुख्यमंत्री से व्यवहार का यही तरीका है? भाजपा की केन्द्र सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि विपक्षी दल हमारे लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें चुप कराने के लिए उनके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।"

इस मामले पर लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया और नीति आयोग को एक "विफल विचार" बताया। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नीति आयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा "नीति आयोग क्या है? यह वह निकाय है जिसे एक विशेष अकादमिक अभ्यास के लिए गठित किया है। इससे क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है? साफतौर से कुछ भी नहीं। योजना आयोग से क्या परेशानी थी? सिर्फ यह कि वह नेहरू के समय से चली आ रही थी, इसलिए नीति आयोग का गठन किया गया। परन्तु आप नेहरू युग की कई चीजों को अभी तक चला आ रहा था।

मीडिया के एक वर्ग ने ममता बनर्जी के नीति आयोग की आज की बैठक में उपस्थित होने के निर्णय को इंडिया गठबंधन में बढ़ती हुई दरार कहा था, क्योंकि विपक्ष-शासित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने "भेदभावपूर्ण बजट प्रस्तावों" के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय किया था। उन्होंने बजट प्रस्तावों को विपक्ष शासित राज्यों की उपेक्षा और उनके साथ भेदभाव करने के समान बताया। इसका बनर्जी ने बैठक में लगभग उसी अंदाज में अपनी बात कही। इससे पूर्व बनर्जी ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात की ओर उन्हें समर्थन का विश्वास दिलाया। कुछ सप्ताह पूर्व उनकी मुम्बई यात्रा के दौरान बनर्जी ने एन.सी.पी. (एस.पी.) के अध्यक्ष शरद पवार एवं शिव सेना (यू.बी.टी.) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- तमिलनाडू के मु.मंत्री स्टालिन ने कहा, ऐसा बर्ताव किसी भी मु.मंत्री से नहीं किया जा सकता। विपक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था का हिस्सा है कोई शत्रु नहीं, जिसे इस तरह चुप कराया जा सकता है।
- लालू यादव ने कहा, "फेल्ड आइडिया" (असफल सोच) है नीति आयोग, योजना आयोग वो ही काम कर रहा था, जो नीति आयोग से अपेक्षा है। मोदी सरकार ने योजना आयोग केवल इसलिये भंग किया क्योंकि यह नेहरू जी के समय गठित हुआ था।
- बहरहाल दिल्ली में ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से उनके घर जाकर मिलीं तथा पूरा समर्थन देने का वादा किया।
- इसी प्रकार वे मुम्बई यात्रा के दौरान वरिष्ठ नेता शरद पवार व उद्धव ठाकरे से भी मिली थीं, विपक्ष में एकता दिखाने के लिये।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने की बड़ी घोषणा

नई दिल्ली/जयपुर, 27 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) के अवसर पर सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समर्पण और राष्ट्र भक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान रखा है।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को देश की सेवा के बाद प्रदेश में भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा।

- अग्निवीरों को राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक के रूप में आरक्षण मिलेगा।

'जब मैं नीति आयोग की बैठक में बोलने लगी तो मेरा माइक बंद कर दिया गया'

प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केन्द्र सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाकर बैठक से वॉकआउट किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। केन्द्र सरकार और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच बढ़ते मतभेद का स्पष्ट नज़ारा नीति आयोग की बैठक में दिखा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकमात्र विपक्षी मुख्यमंत्री थीं जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई थीं, पर जब वो कुछ बोल रही थी उस समय उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया तो वे नाराज़ होकर मीटिंग छोड़कर बाहर आ गईं।

बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में राजनैतिक भेदभाव का आरोप लगाया। गैर भाजपा शासित राज्यों में से सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बैठक में शामिल हुई थीं और इंडिया ब्लॉक के बाकी सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया था।

बनर्जी का दावा है कि उनका माइक म्यूट कर दिय गया और सिर्फ 5 मिनट ही बोलने दिया गया। लेकिन केन्द्र सरकार ने प्रैस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा फैक्ट चैक करवाकर इस दावे को खारिज कर दिया।

बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि, "मैंने कहा था आपको (केन्द्र) राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए मैं बोलना चाहती थी पर मेरा माइक बंद था। मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया पर मुझ से पहले वालों को 10-20 मिनट दिए गए थे। मैंने मीटिंग से वॉक आउट किया है। मैं भविष्य में कभी भी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लूंगी।"

ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मीटिंग में कहा केन्द्र सरकारों को राज्यों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकारें ऐसे नहीं चलतीं। सभी से समान व्यवहार करना चाहिए। भाजपा शासित राज्यों और भाजपा समर्थक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 15-20 मिनट बिना किसी टोकाटाकी के बोलने दिया गया। असम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 10-15 मिनट बोले। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 20 मिनट बोले। बनर्जी ने आगे कहा, "मैं एक मात्र मुख्यमंत्री थी, जो विपक्ष शासित राज्य से थी। उन्हें इसके बारे में खुश होना चाहिए था और मुझे बोलने देना चाहिए था।"

बनर्जी ने कहा कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वह सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है।

विपक्षी दलों ने पूर्व में आरोप लगाया था कि बजट में आंध्र व बिहार पर मेहरबानी की गई क्योंकि केन्द्र सरकार इन दो राज्यों के समर्थन पर टिकी है।

कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया था कि पक्षपाती बजट के विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे।

अन्य विपक्षी दलों ने भी बजट में पक्षपात के खिलाफ नीति आयोग की बैठक में भाग लेने से मना कर दिया था। तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बायकॉट की घोषणा करने की शुरुआत की। उसके बाद कांग्रेस शासित राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना ने भी बैठक के बहिष्कार की घोषणा की और फिर पंजाब, केरल व झारखंड ने भी यही रूख अपनाया।

- मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे।

अनंतनाग में वाहन खाई में गिरा, आठ लोगों की मौत

श्रीनगर, 27 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को एक वाहन के खाई में गिर जाने से पांच बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हादसा डकसुम किश्तवाड़ रोड पर अरशान के पास हुआ।

अधिकारियों ने कहा कि वाहन किश्तवाड़ से डकसुम की ओर जा रहा था, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और खाई में लुढक गया, जिससे एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद, वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतकों में पांच बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं।

मृतकों की पहचान किश्तवाड़ के पुलिसकर्मी इम्तियाज राथर, अफरोजा बेगम, रेशमा और छह से 15 साल की उम्र के बीच के पांच बच्चों के रूप में की गई। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, मनोज

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)